Government of Rajasthan
Mines (Gr-2) Department

No. : प.11(1)(82)खान/ग्रुप-2/2020 Date : 16/10/2020

To

The Hon'ble Chairperson
National Green Tribunal
Principal Bench
New Delhi

RE: Before the National Green Tribunal
Principal Bench, New Delhi
O.A. 575 OF 2019

IN THE MATTER OF:

Yaduraj Singh Jat ... Applicant(s)
Versus
State of Rajasthan ... Respondent(s)

Respected Sir,

1. The above captioned matter pertains to illegal mining of bajri in Banas river which falls within District Karauli and District Baran. This Hon'ble Tribunal vide Order dated 19.02.2020 in the above captioned matter directed the Divisional Commissioners of the concerned areas near River Banas (namely Karauli District and Baran District) to furnish their respective reports through the office of the undersigned. In accordance thereof the same has been filed from time to time.

2. This Hon'ble Tribunal has, independently of this, issued directions from time to time, *inter alia*, in respect of illegal sand mining for which specifically composite directions were in O.A. 606 of 2018. The Government of Rajasthan has been complying accordingly with the directions and several steps as enumerated hereinunder have been taken:

   i. A Chief Secretary's Environment Cell has been established which is monitoring all the cases.

ii. The office of the Chief Secretary is holding regular meetings with the District Magistrates. On 28.02.2020, there was a meeting held with the Director General of Police (Law and Order), Secretary Home, Director Mines, all District Collectors, Dy. Conservator of Forest and other concerned officers. The office of the undersigned has issued several directions including formation of S.I.T., regular monitoring of cases registered against illegal mining, special check posts on the routes routinely used for illegal mining, ensuring CCTV surveillance, strict recovery of environmental compensation fee, etc. A meeting was also conducted on 12.10.2020 wherein directions were issued to the District Magistrates to create awareness at the Panchayat level by calling meetings of the concerned functionaries.

iii. The office of the Chief Secretary along with officers of concerned departments is in the process of issuing comprehensive guidelines applicable to all cases in the State of Rajasthan.

iv. The Mining Department has also taken up the project of creating a redressal portal and a mobile application for reporting, etc. of illegal sand mining activities.

3. The office of the undersigned is regularly monitoring the steps to curb illegal sand mining in the State of Rajasthan in compliance with the directions of the Hon'ble Supreme Court of India, this Hon'ble Tribunal and the Hon'ble High Court of the Rajasthan.

4. In respect of the above captioned matter, the Reports as received from the Divisional Commissioners of Kota Division and Bharatpur Division, are annexed herewith and marked as Annexure – 1 and 2 respectively.

Regards,

(Rajeeva Swarup)
Chief Secretary
Government of Rajasthan

Encl.

Annexure – 1: Report of the Divisional Commissioner, Kota Division

Annexure – 2: Report of the Divisional Commissioner, Bharatpur Division

ANNEXURE-1

प्रमांक:प-4( )रा.आ./स्टाद/2020/525

राजस्थान सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त, कोटा संभाग, कोटा

सीएडी भवन, कोटा-324009, दूरभाष:0744-2500853,675 फैक्स:2500769, Email : divcomm-kota-rj@nic.in

कोटा, दिनांक: 18.5.2

निदेशक
खान एवं भूविज्ञान विभाग,
राजस्थान उदयपुर। 313001

विषयः—ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 575/2019 यदुराज सिंह जाट बनाम राजस्थान राज्य माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली।
प्रसंगः—आपका पत्र कमांक प.11(1)(82)खान/ग्रुप—2/2020/6.3.2020 एवं 12.05.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के कम में जिला कलक्टर कोटा, बून्दी, बारां एवं झालावाड से प्राप्त रिपोर्टस की छायाप्रतियां पत्र के साथ सलंग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सलंग्न—उपरोक्तानुसार

6681
3-6-2020

(कैलाश चन्द मीना)
संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

कमांक/समसंख्यक/ दिनांक 18.05.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सलंग्न कर प्रेषित हैः—

1 संयुक्त शासन सचिव, खान (ग्रुप=2)विभाग,जयपुर।
2 राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, 4 इण्डस्ट्रीयल एरिया झालाना डूंगरी जयपुर।

सलंग्न- उपरोक्तानुसार

अति० संभागीय आयुक्त
कोटा

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, बारां

क्रमांक एफ–4( )राजस्व/अ.ख./2020/1469 दिनांक:– 15 मई, 2020

निमित्त:–

अति0 संभागीय आयुक्त,
कोटा संभाग, कोटा।

विषय :–ओरिज़नल एप्लीकेशन संख्या 575/2019 यदुराज सिंह जाट बनाम राज0 राज्य माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली।

प्रसंग :–आपका पत्र क्रमांक :प–4( )सं.आ./न्याय/2020/125 दिनांक 14.05.2020

महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के निर्णय दिनांक 19.02.2020 की पालना में पूर्ण तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गयी है।

प्रासंगिक पत्र द्वारा चाही गयी सूचना पूर्व में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 16.03.2020 से भिजवाने के पश्चात् पत्र दिनांक 23.03.2020 से पूर्ण सूचना भिजवायी जा चुकी है, जिनकी छायाप्रतियां पुनः प्रेषित है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

भवदीय

(मोहम्मद अबूबक्र)
अति0 जिला कलक्टर,
बारां

15.5.20

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, बारां

क्रमांक एफ–4( )राजस्व/अ.ख./2020/ /283 दिनांक– 23 मार्च, 2020

निमित्त:–

श्रीमान् संभागीय आयुक्त,
कोटा संभाग, कोटा।

विषय :–ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 575/2019 यदुराज सिंह जाट बनाम राज0 राज्य माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि बजरी अवैध खनन से संबंधित रिपोर्ट चाही गयी है जो निम्नानुसार प्रेषित है–

बारां जिला में मुख्य रूप से पार्वती, परवन, अण्डेरी, रेतली क्षेत्र में खनिज बजरी उपलब्ध है यह बजरी काले रंग की कम गुणवत्ता की होने से मुख्यतय: स्थानिय स्तर पर चुनाई के काम में ली जाती है। इन नदियों में स्थानीय ग्रामीणो द्वारा अवैध खनन से खनिज बजरी आस–पास के गांव में अवैध रूप से बेची जाती है। खनिज बजरी के खनन स्वीकृति के संबंध में एंव बजरी के अवैध खनन के विरूद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है–

1. <u>बजरी के खननपट्टो की स्वीकृति हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण :–</u>

बारां जिले की तहसील मांगरोल व तह0 किशनगंज में बहने वाली गैरमुमकीन नदी(पार्वती) में विभाग द्वारा खनिज बजरी के खननपट्टे हेतु एक मंशापत्र दिनांक 24.12.13 कुल क्षेत्रफल 329.90 है. के लिए श्री प्रमोद मीणा के नाम जारी किया गया । मंशापत्र धारी द्वारा पर्यावरण पूर्वानुमति हेतु वन एंव पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार में आवेदन किया है जो लंबित है। मंशापत्र धारी के पक्ष में अस्थायी कार्यानुमति जारी नही की गयी है। तथा इसी प्रकार तह0 बारां व किशनगंज में बहने वाली गैरमुमकीन नदी(पार्वती) विभाग द्वारा खनिज बजरी के खननपट्टे हेतु एक मंशापत्र दिनांक 03.12.2014 कुल क्षेत्रफल 360.97 है. के लिए श्री मुकेश शर्मा के नाम जारी किया गया । मंशापत्र धारी द्वारा पर्यावरण पूर्वानुमति हेतु वन एंव पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार में आवेदन किया है जो लंबित है। मंशापत्र धारी के पक्ष में अस्थायी कार्यानुमति जारी नही की गयी है।

बारां जिले की तहसील अटरू में बहने वाली गैरमुमकीन नदी (परवन/पार्वती) में खनिज बजरी के खननपट्टे हेतु श्री मनोज जैन के पक्ष में मंशापत्र दिनांक 24.01.2013 कुल क्षेत्रफल 159.27 है0 के लिए जारी किया गया । मंशापत्र धारी द्वारा पर्यावरण पूर्वानुमति हेतु वन एंव पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार में आवेदन किया है जो लंबित है। मंशापत्र धारी के पक्ष में अस्थायी कार्यानुमति दिनांक 23.12.13 से 17.11.17 तक जारी की गयी थी ।

पता : मिनी सचिवालय, बारां (326205)
Ph. No. : (07453) 237001, 237003 (Fax) 237005
E-mail ID : dlt-brn-rj@nic.in
admbaran@gmail.com

Scanned with CamScanner

2. <u>बजरी अवैध खनन के प्रोन क्षेत्र(तहसीलवार) –</u>

1. तहसील बारां– ग्राम कल्याणपुरा , घीसरी, मेहपुरा, कोयला आदि गांव जो पार्वती नदी के पास बसे हुए गांव।
2. तहसील किशनगंज– ग्राम कामठा , रानीबडौद, दडपुरा , किशनगंज, जलवाडा आदि पार्वती नदी के किनारे बसे हुए. गांव ।
3. तहसील अंता–ग्राम रायपुरिया, गुलाबपुरा, चहेडिया, बालदडा आदि कालीसिंध , परवन नदी एंव परवन नदी के किनारे बसे हुए क्षेत्र ।
4. तहसील मांगरोल– ग्राम मुण्डिया , नंदगावडी, सिंगोला बालुंदा , ईश्वरपुरा आदि पार्वती नदी के गांव एंव ग्राम सींसवाली भैरूपुरा कनाडा , पापडली आदि क्षेत्र।
5. तहसील छबडा–ग्राम पचपाडा , नीमथूर, चावलखेडी, गुगोर, कन्हैयावन, भीलवाडा उंचा–नीचा आदि क्षेत्र।
6. तहसील छीपाबडौद– ग्राम टांचा–टांची, गगचाना, मेहपुरा, पछाड आदि ल्हासी व अन्धेरी नदी किनारे बसे गांव ।
7. तहसील अटरू – ग्राम गुलखेडी , फूलबडोदा, पींपलोद , दैगनी, गचघाट, कुण्डी, पाडलिया, आदि क्षेत्र।

3. <u>बजरी के अवैध खनन/परिवहन के विरूद्व की गयी कार्यवाही–</u> बजरी के अवैध खनन/परिवहन /स्टॉक के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय सिविल रिट पिटिशन संख्या 9458/2018 में पारित आदेश दिनांक 03.05.2018 की पालना में राजस्व , पुलिस, वन, परिवहन व खनिज विभाग के अधिकारियो की विशेष अन्वेषण टीमो का गठन अधोहस्ताक्षरकर्ता के आदेश दिनांक 17.07.2018 से किया गया जिसमें जिला स्तरीय व उपखण्ड स्तरीय विशेष जांच दलों के साथ बजरी के अवैध खनन/परिवहन /स्टॉक के विरूद्ध कार्यवाही की जाती रही है। बजरी के खनन पर प्रतिबंध के पश्चात् निम्नानुसार कार्यवाही की गयी।

क.	विवरण	कुल प्रकरण	दर्ज एफ0 आई0 आर0	वसूल की गयी राशि	जब्त किये औजार, मशीन वाहन इत्यादि
1	दि0 16.11.17 से 31.03.18	77	0	3654350	0
2	वर्ष 2018–19	116	0	5294550	0
3	वर्ष2019–20(18.03.2020 तक)	226	5	9447188	14

एस0आई0टी0 बारां द्वारा माह जुलाई, अगस्त 2019 में अभियान चलाकर निर्माण स्थलो पर पाये गये कुल 32 अवैध स्टॉक बजरी के जब्त किये गये थे तथा आगामी कार्यवाही के कम में तत्कालीन सहायक खनि अभियंता, बारां द्वारा कुछ अवैध स्टॉक कर्ताओ को नोटिस जारी कर दिये गयें थे जिसकी पालना में कुछ अवैध स्टॉक कर्ताओ द्वारा पेनल्टी के चालान कार्यालय में जमा कर दिये गये है। मगर बजरी मुक्त किया जाना शेष है। कुछ अवैध स्टॉककर्ताओ द्वारा पैनल्टी राशि जमा नही करवायी गयी है। इसी कम में दिनांक 0.. 08.2019 को एस0आई0टी0 बारां की बैठक में जब्तशुदा बजरी की नीलामी किये जाने का निर्णय लिया गया है। लेकिन पेनल्टी राशि जमा कराने वाले स्टॉक कर्ताओ के संबंध में कोई

Scanned with CamScanner

चर्चा नही की गयी कि उनकी बजरी मुक्त किया जावें अथवा नीलाम किया जावे। एस0आई0टी0 बारां की बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 03.03.2020 के कम में एकरूपता बनाये रखने की दृष्टि से जब्तशुदा बजरी के निस्तारण/नीलामी के संबंध में दिशा–निर्देश हेतु सहायक खनि अभियंता, बारा के पत्रांक 521 दिनांक 11.03.2020 से अधीक्षण खनि अभियंता, कोटा से मार्गदर्शन चाहा गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 19.02.2020 की पालना में श्रीमान मुख्य सचिव, राजस्थान–सरकार जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 28.02.2020 को विडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये राज्य स्तरीय बैठक ली गयी जिसमें समस्त जिलों के जिला कलक्टर व पुलिस अधीक्षक सहित राजस्व, पुलिस, खनिज, परिवहन, वन विभागो के उच्च स्तरीय अधिकारी शामिल हुये । बैठक कार्यवाही रिपोर्ट प्रति संलग्न है। श्रीमान मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान की उक्त बैठक दिनांक 28.02.2020 की अनुपालना में बारां जिले में अधोहस्ताक्षरकार्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय व उपखण्ड स्तरीय राजस्व, पुलिस, वन, खनिज, परिवहन विभागों के अधिकारियों की विडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये बैठक दिनांक 28.02.2020 को ली गयी(बैठक कार्यवाही रिपोर्ट संलग्न है।) वर्तमान में जिला स्तर व उपखण्ड स्तर पर गठित टीमो खनिज बजरी के अवैध खनन/परिवहन/स्टॉको विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

भवदीय

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर, बारां

Scanned with CamScanner

ANNEXURE-1

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR, BARAN

Sr. No.F-4( )Revenue/I.M./2020/1283 Date: 23.03.2020

For

The Divisional Commissioner

Kota Division, Kota

Subject:- Original Application No.575/2019 titled as Yaduraj Singh Jat versus State of Rajasthan before the Hon`ble National Green Tribunal, New Delhi

Sir,

It is respectfully submitted in the above referenced subjected letter that a report in respect of the illegal Bajri mining has been sought, which is sent in the following manner:-

Mineral Bajri is available mainly in Parwati, Parwan, Anderi, Retli areas of District Baran. Since this bajri being black in colour and of poor quality therefore it is mainly used for masonry purpose at the local level. The local villagers by carrying out illegal mining in these rivers thereafter illegally sell the mineral bajri in the nearby villages. The details in respect of the approval for mining of mineral bajri and the action taken against illegal mining of bajri is as following:-

1. **Details of the action taken for the purpose of approval of the mining lease for bajri:-**

   The Department for the purpose of mining lease of mineral bajri from the Gair Mumkin Nadi (Parwati) flowing through Tehsil Mangrol and Tehsil Kishanganj of District Baran issued a letter of intent on 24.12.13 in the name of Shri Pramod Meena for a total area of 329.90 Hec. The holder of Letter of intent for the purpose of obtaining environmental clearance has applied with the Ministry of Environment and Forest, Government of India which is still pending. No temporary work order has been issued in favour of the holder of Letter of intent and similarly, the Department for the purpose of mining lease of mineral bajri from the Gair Mumkin Nadi (Parwati) flowing through Tehsil Baran and Tehsil Kishanganj issued a letter of intent on 03.12.2014 in the name of Shri

Mukesh Sharma for a total area of 360.97 Hec. The holder of Letter of intent for the purpose of obtaining environmental clearance has applied with the Ministry of Environment and Forest, Government of India which is still pending. No temporary work order has been issued in favour of the holder of Letter of intent.

A letter of intent for the purpose of mining lease of mineral bajri from the Gair Mumkin Nadi (Parwan/Parwati) flowing through Tehsil Atru of District Baran was issued on 24.01.2013 in the name of Shri Manij Jain for a total area of 159.27 Hec. The holder of Letter of intent for the purpose of obtaining environmental clearance has applied with the Ministry of Environment and Forest, Government of India which is still pending. A temporary work order has been issued in favour of the holder of Letter of intent valid from dated 23.12.13 till dated 17.11.17.

2. Areas prone to illegal mining of bajri (Tehsilwar):-

1. Tehsil Baran:- Village Kalyanpura, Ghisri, Mehpura, Koyala etc. villages which are villages in habited near Parvati river.

2. Tehsil Kishanganj:- Village Kamtha, Rani Barod, Dadpura, Kishanganj, Jalwada etc. inhabited on the banks of river Parvati.

3. Tehsil Anta- Village Raipuriya, Gulabpura, Chahedia, Baldada etc. Kalisindh, Parwan River and areas inhabited on the banks of Parwan river.

4. Tehsil Mangrol- Village Mundia, Nandgawdi, Singola, Balunda, Ishwarpura etc. villages situated near Parwati River and areas of village Siswali, Bherupura, Kanada, Papdali etc.

5. Tehsil Chhabra- Village Pachpada, Nimthur, Chawalkhedi, Gugor, Kandeyavan, Bhilwara unlevelled areas etc.

6. Tehsil Chhipabarod- Village Tancha-Tanchi, Gagchana, Mehpura, Pachaad etc. Lahasi and villages inhabited on the banks of river Anderi.

7. Tehsil Atru- Village Gulkhedi, Phulbaroda, Piplod, Degni, Gaughat, Kundi, Padlia etc. areas.

3. **Action taken against illegal mining/transportation of bajri:-** In compliance of the order dated 03.05.2018 passed by the Hon'ble Rajasthan High Court in the Civil Writ Petition No.9458/2018 instituted against illegal mining/transportation/storage of bajri, Special Investigation Teams comprising of the officers from the Revenue, Police, Forest, Transport and Mines Department was formed vide the order of the undersigned dated 17.07.2018 wherein the Special Investigation Team at the District Level and the Sub-District Level have continued to take action against the illegal mining/transportation/storage of bajri. After restriction on the mining of bajri action were taken in the following manner:-

S. No.	Details	Total No. of cases	FIR lodged	Amount recovered	Seized Tools, machinery, vehicle etc.
1	Dated 16.11.17 till 31.03.2018	77	0	3654350	0
2	Year 2018-19	116	0	5294550	0
3	Year2019-20 (till Dated 18.03.2020)	226	5	9447186	14

S.I.T. by running a drive in the month of July, August, 2019 seized a total of 32 illegal stocks of bajri recovered from construction sites and in sequence of further proceedings the then Assistant Mining Engineer, Baran had issued notices to some "illegible" and in compliance of which some stockiest have deposited the penalty amount of challan with the office but the bajri is yet to be released. Some illegal stockiest have failed to deposit the penalty amount. In the same sequence on 09.08.2019 during the meeting of S.I.T. Baran it was decided for auction of the seized bajri. But no discussion was held in respect of the stockiest who have deposited the penalty amount whether their bajri is to be released or to be auctioned. With the view of maintaining uniformity in sequence of the minutes of the meeting of the S.I.T. Baran dated 03.03.2020 for the purpose of directions in respect of the disposal/auction of the seized bajri, vide the Letter No.521 Dated 11.03.2020 guidance was sought by the Assistant Mining Engineer from the Superintendent Mining Engineer, Kota.

In compliance of the Hon'ble Supreme Court Order Dated 19.02.2020, on 28.02.2020 in the Chairmanship of Respected Chief Secretary Government of Rajasthan Jaipur a State Level meeting was organized through video conferencing wherein all the District Collectors of every district and Superintendent of Police along with High Level Officers of the Revenue, Police, Mines, Transport, Forest Departments took part. A copy of report on the minutes of the meeting is enclosed. In compliance of the meeting of the Respected Chief Secretary, Rajasthan held on 28.02.2020, a meeting of the officers from the District Level and Sub-Division Level officers of the Revenue, Police, Forest, Mines, Transport Departments was held on 28.02.2020. (A report of the minutes of the meeting is enclosed). At present action is being taken by the teams formed at the District and Sub-Division Level against the illegal mining/transportation/stocks of mineral bajri.

Enclosures:- As above

Regards

Sd/-

(Indra Singh Rao)

District Collector, Baran

True Translated Copy

ANNEXURE-2

कार्यालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

क्रमांक/राजस्व/2020/174 दिनांक :- 11/03/2020

निदेशक
खान एवं भू-विज्ञान विभाग
राजस्थान, उदयपुर

विषय :-ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 575/2019 यदुराज सिंह जाट बनाम राजस्थान राज्य, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली।
प्रसंग :- संयुक्त शासन सचिव, खान (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर का पत्रांक प-11(1)(82)खान/ग्रुप-2/2020 दिनांक 06.03.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि उक्त प्रकरण बनास नदी करौली (राजस्थान) में हो रहे बजरी के अवैध खनन से सम्बन्धित रिपोर्ट संभागीय आयुक्त जरिये मुख्य सचिव महोदय को प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये है। उक्त पत्र की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भी पृष्ठांकित की गई है। इसी क्रम में जिला कलक्टर करौली से प्राप्त बिन्दुवार रिपोर्ट आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है ताकि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश की अनुपालना की जा सकें।

संलग्न :- जिला कलक्टर करौली
से प्राप्त बिन्दुवार रिपोर्ट कुल पृष्ठ- 7

भवदीय,

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर
दिनांक :- 11/03/2020

क्रमांक/सम/175-77
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-
1. श्री कमलेश सिंह चौहान संयुक्त शासन सचिव, खान (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. जिला कलक्टर करौली।
3. अतिरिक्त निदेशक (खान) खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जयपुर।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर 11/3

कार्यालय जिला कलक्टर करौली

कमांक/प.12(3)(4)(2)खनिज/2020/ 546 दिनांकः 06/03/2020

श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय,
संभाग भरतपुर।

विषयः– ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 575/2019 यदुराज सिंह जाट बनाम राजस्थान राज्य, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली

प्रसंगः– आपका पत्र पत्रांक/राजस्व/2020/168 दिनांक 06.03.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न संयुक्त शासन सचिव, (ग्रुप–2) खान विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र एवं ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 575/2019 यदुराजसिंह जाट बनाम राजस्थान राज्य, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेश कमांक 19.02.2020 के कम मे बिन्दूवार रिपोर्ट निम्न प्रकार है :–

1. बिन्दू संख्या 01 राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल से सम्बन्धित है।
2. बिन्दू संख्या 02 के कम मे निवेदन है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 16.11.17 से राजस्थान राज्य मे खनिज बजरी की स्वीकृत 82 एलओआई मे जिला करौली मे स्वीकृत 01 एलओआई श्री रमेशचन्द मोरानी के पक्ष मे निकट ग्राम हाडौती तहसील सपोटरा क्षेत्र 894.5 है हेतु स्वीकृत थी उक्त एलओआई माननीय हरित प्राधिकरण भोपाल के आदेश दिनांक 24.05.2016 की पालना मे दिनांक 27.05.1016 से खनन कार्य बन्द करवाया गया।

   माननीय उच्च न्यायालय जयपुर मे दायर सिविल रिट पिटीशन संख्या 9458/2017 मे पारित आदेश दिनांक 03.05.18 के कम मे इस कार्यालय के द्वारा दिनांक 17.07.2018 के द्वारा खनिज, वन, परिवहन, राजस्व एवं पुलिस विभागो का संयुक्त विशेष दल का गठन किया गया है। उक्त संयुक्त जॉच दल द्वारा जिला करौली मे खनिज बजरी के अवैध खनन स्थल मुख्यतया तहसील सपोटरा के ग्राम हाडौती एवं आसपास के क्षेत्रो मे बहने वाली बनास नदी क्षेत्र मे खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारन के विरूद्व नियमित रूप से कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त जिले मे ग्राम बूकना मोड, चौडागॉव (जोडली मोड), पानेटा एवं गुलाब कोठी एवं नारौली डॉग तहसील सपोटरा मे पुलिस एवं खनिज विभाग की संयुक्त चौकिया स्थापित की गई है तथा वर्तमान मे ग्राम पंवारपुरा, फतेहपुरा, हाडौती से भूरी पहाडी पर स्थित पुल, पंवारपुरा नदी एवं बडौदा गजराजपाल पर चैक पोस्ट/नाके लगाये जाकर सीसीटीवी कैमरे स्थापित किये गये है। उक्त चैक पोस्टो के स्थापित होने के पश्चात् खनिज बजरी का अवैध खनन/निर्गमन लगभग नगण्य हो गया है।

Rev
M
11/3/20

इसके अतिरिक्त समय–समय पर संयुक्त रूप से (पुलिस विभाग, खनिज विभाग, राजस्व विभाग, परिवहन विभाग, वन विभाग) आपसी समन्वय स्थापित कर क्षेत्र मे अवैध बजरी खनन एवं परिवहन को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर आयोजित की जाने वाली साप्ताहिक बैठक मे भी राजस्व, पुलिस, खान, वन एवं परिवहन विभाग को अधिकारियो आपसी समन्वय स्थापित कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है। इस सम्बन्ध मे इस वर्ष की गई कार्यवाही निम्न प्रकार है :–

अवधि 01.04.2019 से 06.03.2020 तक

क्र0 स0	विभाग का नाम	प्रकरणो की संख्या जिनमे कार्यवाही की गई	प्रकरणो मे वसूल की गई राशि लाखो मे	कितने प्रकरणो मे पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराई गई	विशेष विवरण
1.	खनिज विभाग	257	141.18	8	अवैध खनन 2 अवैध निर्गमन 247 अवैध स्टॉक 6
2.	पुलिस विभाग	185	–	मुकदमे 33 207 एम.बी.एक्ट 130 38 पुलिस एक्ट 27	
3.	परिवहन विभाग	98	9.12 लाख	–	ट्रक 32 ट्रेलर 8 ट्रैक्टर 58
कुल		540	150.30		

संलग्न– खनिज,पुलिस एवं परिवहन
विभाग की रिर्पोटो की प्रति

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
करौली

क्रमांक/सम/2020/ दिनांक 06.03.2020

प्रतिलिपी –

1. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महोदय, खान (ग्रुप–2) विभाग राजस्थान जयपुर।

हस्ता.
अतिरिक्त जिला कलक्टर
करौली

कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, करौली

क्रमांक :- 2760 दिनांक :- 06/03/20

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,
करौली

विषय :- ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 575/2019 यदुराज सिंह जाट बनाम राजस्थान राज्य माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली।

प्रसंग :- श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, खान (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर का पत्रांक प-11(1) (82) खान/ग्रुप-2/2020 दिनांक 06.03.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जिले में उडनदस्तों द्वारा बजरी के ओवरलोड परिवहन पर माह अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 तक की गई कार्यवाही की रिपोर्ट निम्नानुसार तैयार कर सादर प्रेषित है :-

क्र.सं.	वाहन का प्रकार	चालानों की संख्या	राशि (लाखों में)
1	ट्रक	32	2.41
2	ट्रेलर	8	1.49
3	ट्रैक्टर	58	5.22
	योग	98	9.12

जिला परिवहन अधिकारी
करौली (राज0)

राजस्थान सरकार

भीमे

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, करौली

जिला परिषद कार्यालय एवं सिटी पार्क के पास खनिज भवन
Mail Id- me.karoli@rajasthan.gov.in tele. No. 07464-250202

क्रमांक:–खअ/करौ/बजरी एसआईटी/2020/34 दिनांक :– 6.3.20

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर,
जिला करौली।

विषय :– ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 575/2019 यदुराज सिंह जाट बनाम राजस्थान राज्य, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली।
प्रसंग :– आपका पत्रांक प.12(3)(4)(2) खनिज/2020/542 दिनांक 06.03.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 575/2019 यदुराज सिंह जाट बनाम राजस्थान राज्य, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेश दिनाक 19.02.2020 की पालना में बिन्दुवार जवाब निम्न प्रकार है :–

1. बिन्दु संख्या 1 में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल एवं मध्यप्रदेश राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल से प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट चाही गयी है जो इस कार्यालय से संबंधित नहीं होने के कारण कार्यालय की कोई टिप्पणी अपेक्षित नही है।
2. बिन्दु संख्या 2 के संदर्भ में टिप्पणी निम्न प्रकार है:–

माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा DBCMA No 250/2013 में पारित आदेश दिनांक 21.10.2013 के विरूद्व याचिकाकर्ता श्री नवीन शर्मा द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्पेशल लीव टू अपील संख्या 34811/2013 दायर की गयी उक्त दायर एसएलपी पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 16.11.2017 से आदेश जारी कर राजस्थान राज्य में खनिज बजरी की स्वीकृत 82 एलओआई में खनिज बजरी के खनन पर रोक लगायी गयी । उक्त 82 एलओआई में जिल में स्वीकृत 01 एलओआई जो श्री रमेश चन्द मोरानी के पक्ष निकट ग्राम हाडोती तहसील सपोटरा क्षेत्र 894.5 है0 हेतु स्वीकृत थी उक्त एलओआई माननीय हरित प्राधिकरण भोपाल के आदेश दिनांक 24.5.2016 की पालना में दिनांक 27.5.2016 से खनन कार्य बंद करवाया गया।

उक्त आदेश के पश्चात् खनिज बजरी के वैध स्त्रोत में खनन कार्य पर रोक होने के कारण खनिज बजरी के अवैध खनन /निर्गमन की शिकायते कार्यालय को प्राप्त होने लगी जिस पर कार्यालय द्वारा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के तहत खनिज बजरी को अवैध मानते हुये कार्यवाही की जाती रही।

तत्पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष दायर SBCWP No 9458/2017 संजय कुमार गर्ग बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 03.5.2018 में दिये गये निर्देशो की पालना में खनिज बजरी के अवैध खनन / परिवहन / भण्डारण की रोकथाम हेतु श्रीमान जिला कलक्टर करौली के आदेश दिनांक 17.7.2018 से खनिज, वन, परिवहन, राजस्व एवं पुलिस विभागो का संयुक्त विशेष जॉच दल का गठन किया गया ।

Demand 751

उक्त संयुक्त जॉच दल द्वारा जिला करौली में खनिज बजरी के अवैध खनन स्थल मुख्यतया तहसील सपोटरा के ग्राम हाडौती एवं आसपास के क्षेत्रो में बहने वाली बनास नदी क्षेत्र में खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरूद्व नियमित रूप से कार्यवाही की जाती रही ।

उपरोक्त के अतिरिक्त जिले में खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन के क्षेत्र में निकट ग्राम बूकना मोड, चौडागांव (जोडली मोड), रानेटा एवं गुलाब कोठी एवं नारौली डांग तहसील सपोटरा में पुलिस एवं खनिज विभाग की संयुक्त चौकिया स्थापित की गयी। जिनका निरन्तर रूप से श्रीमान जिला कलक्टर, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं खनि अभियन्ता करौली द्वारा निरीक्षण किया जाता है।

माननीय न्यायालय के आदेशो की पूर्ण पालना सुनिश्चित करने हेतु श्रीमान जिला कलक्टर महोदय एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार उक्तानुसार स्थापित चौकियों के स्थान पर वर्तमान में ग्राम चमारपुरा, फतेहपुरा, हाडौती से भूरी पहाडी पर स्थित पुल, पवांरपुरा नदी एवं बडौदा गजराजपाल पर चैक पोस्ट /नाके लगाये जाकर सीसीटीवी कैमरे स्थापित किये गये है । उक्त चैक पोस्टो के स्थापित होने के पश्चात् खनिज बजरी का अवैध खनन/निर्गमन लगभग नगण्य हो गया है।

कार्यालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 16.11.2017 के पश्चता् खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/के विरूद्व की गयी कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्रंस	विवरण	अवैध खनन	अवैध निर्गमन	अवैध स्टाक	कुल प्रकरण	वसूल की गयी राशि लाखो में	दर्ज एफआईआर
1	दिनांक 16.11.17 से 31.03.2018	0	29	0	29	13.69	1
2	वर्ष 2018–19	2	214	7	223	70.46	24
3	वर्ष 2019–20 (दिनांक 29.02.2020 तक)	2	247	6	255	129.25	8
	6/3/2020 तक	~	257	✓	265	141.16	✓

3. बिन्दु संख्या 3 की पालना में कार्यालय की टिप्पणी अपेक्षित नही है।
4. बिन्दु संख्या 4 की पालना में कार्यालय की टिप्पणी अपेक्षित नही है।

भवदीय

(डी.एस.मीना)
खनि अभियन्ता
करौली

।। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला करौली ।।

क्रमांकः- विविध/करौली/2020/2073 दिनांकः- 6.3.2020

जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट
करौली।

विषयः--ओरीजन एप्लीकेशन संख्या 576 यदुराज सिंह जाट बनाम राजस्थान राज्य माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली।

प्रसंगः--श्रीमान के पत्र कमांक/प.12 (3)(4)(2) खनिज/2020/544--45 दिनांक 6.3.2020 के संदर्भ में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रसंग में निवेदन है कि जिला करौली बनास नदी/चम्बल नदी में हो रही बजरी के अवैध खनन/निर्गमन के रोकथाम के संबंध में वर्ष 2019 व 05 मार्च 2020 तक निम्न प्रकार कार्यवाही की गई जो अवलोकनार्थ प्रेषित है।

वर्ष 2019 में अवैध बजरी के संबंध में सूचना

मुकदमा	207 एम.बी. एक्ट	38 पुलिस एक्ट
29	109	22

01.01.2020 से 05.03.2020 तक अवैध बजरी के संबंध में सूचना

मुकदमा	207 एम.बी. एक्ट	38 पुलिस एक्ट
04	21	05

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका (सिविल) 10587/2019 बजरी लीज एलओआई होल्डर बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 19.02.2020 की पालना में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा में दिनांक 29.02.2020 को 2.00 पीएम पर जिला स्तरीय एस.आई.टी. की बैठक का आयाजित करने का निर्णय किया गया।

उक्त निर्णय कि पालना में दिनांक 29.02.2020 को समय 10.00 एएम पर मनं पुलिस अधीक्षक एवं श्रीमान जिला कलक्टर करौली, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करौली, उपखण्ड अधिकारी सपोटरा, खनिज अभियन्ता करौली एवं अन्य संबंधित जिला स्तरीय एसआईटी सदस्य/अधिकारीयों द्वारा संयुक्त रूप से जिले की तहसील सपोटरा में खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन की रोकथाम हेतु पूर्व में लगायी गयी आएसी की स्थायी चैक पोस्ट बूकना मोड, चौडागॉव (जोडली मोड), रानेटा एवं गुलाब कोठी का निरीक्षण किया गया।

तत्पश्चात् संयुक्त टीम द्वारा सर्वप्रथम खनिज बजरी के अवैध खनन का मुख्य क्षेत्र ग्राम पवारपुरा तहसील सपोटरा एवं खनिज बजरी के अवैध निर्गमन के मुख्य मार्ग ग्राम फतेहपुरा, बडौदा गजराजपाल, चमारपुरा का निरीक्षण किया गया।

क्षेत्रीय निरीक्षण के बाद कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा में समय 2.00 पीएम पर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन /भण्डारण हेतु जिला स्तर व थाना स्तर पर गठित पर गठित एसआईटी की बैठक आयोजित की गयी। उक्त बैठक में निम्न सुझाव पारित हुएः--

1. पूर्व में स्थापित चौकियों बूकना मोड, चौडागांव (जोडली मोड), रानेटा, एवं गुलाब की कोठी को हटाकर नदी क्षेत्र (खनिज बजरी अवैध खनन स्थल) ग्राम पवारपुरा एवं बनास नदी में स्थित हाडोती (जिला करौली) से भूरी पहाडी (जिला सवाईमाधोपुर) के मध्य स्थित पुल एवं अवैध निर्गमन के मुख्य रास्ते ग्राम फतेहपुरा, बडौदा गजराजपाल एवं चमारपुरा पर आरएसी के साथ चौकी लगायी जावे ताकि खनिज बजरी के अवैध खनन स्थल तक कोई वाहन/मशीन नहीं पहुंच सके। जिससे अवैध खनन/निर्गमन में गिरावट की पूर्ण संभावना है।
2. खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन की रोकथाम हेतु चमारपुरा, फतेहपुरा, हाडौती से भूरी पहाडी पर स्थित पुल, पवांरपुरा नदी एवं बडौदा गजराजपाल पर चैक पोस्ट/नाके लगाये जाकर उन चैक पोस्टों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने हेतु खनि अभियन्ता, करौली को निर्देश दिये गयें जिससे अवैध निर्गमनकर्ताओं में भय व्याप्त किया जा सके। जिस पर खनि अभियन्ता करौली द्वारा उक्तानुसार चैक पोस्टों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया गया।
3. मीटिंग में जिला/थाना स्तर पर गठित एसआईटी द्वारा संयुक्त रूप से 15 मार्च से पूर्व कम से कम 4 बडी कार्यवाही एवं खनिज बजरी के अवैध स्टॉक को जप्त करने की कार्यवाही के साथ-साथ सम्बन्धित दोषियों के विरूद्ध पीडीपीपी एक्ट की धाराओं के अनुसार भी कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।
4. जिले में खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन में लिप्त खनन माफियाओं का चिन्हिकरण कर उनके द्वारा अवैध खनन/निर्गमन में उपयोग किये जाने वाले वाहन/मशीनों को जप्त कर संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराने हेतु का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त लिये गये निर्णयों के संदर्भ में अवैध बजरी खनन/निर्गमन की रोकथाम हेतु हाडौती बनास नदी चैक पोस्ट, कंवारपुरा चैक पोस्ट, गढी का गांव चैक पोस्ट, खुशालसिंह तिराहा चैक पोस्ट, बडोदा गजराजपाल चैक पोस्ट स्थाई चौकी स्थापित की जाकर उनमें पुलिस विभाग, खनन विभाग व वन विभाग के मुलाजमान पदस्थापित किये जा चुके है। उक्त पांचों स्थाई चौकियों में सीसीटीवी कैमरा लगाये जा चुके है। इसके अलावा फतेहपुर, हाडौती तिराया, गोरधनपुरा पर थाना सपोटरा व पुलिस लाईन से अस्थाई गार्ड लगाई गई है जिनमें पुलिस मुलाजमान तैनात किये गये है।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
जिला पुलिस अधीक्षक,
करौली

ANNEXURE-2

Office of the Divisional Commissioner, Bharatpur

Sr. No./Revenue/2020/174 Date: 11.03.2020

Director
Mines and Geology Department
Rajasthan, Udaipur

Subject: Original Application No.575/2019 titled as Yaduraj Singh Jat versus State of Rajasthan before the Hon`ble National Green Tribunal, New Delhi

Reference: In reference to the Joint Secretary to Government, Mining (Group-2) Department, Rajasthan Jaipur Letter no.P-11(1)(82) Mining/Group-2/2020 Dated 06.03.2020.

Sir,

It is submitted in sequence of the above subjected and referenced letter that directions were issued in the said case for submitting a report through Divisional Commissioner to the Chief Secretary in respect of illegal sand mining being carried out over Karauli river in Rajasthan. A copy of the said

letter was also endorsed to the undersigned. In the same sequence, a point wise report received from the District Collector Karauli is being dispatched to you for the purpose of necessary action such that order of the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi is duly complied with.

Enclosures:- Point wise report received from the District Collector, Karauli, Total No. of Pages-7.

Regards
Sd/- illegible
(Chandra Shekhar Mutha)
Divisional Commissioner
Bharatpur

Sr. No./Even/175-77 Date: 11.03.2020

Photocopy to the following for information and taking necessary action:-

1. Shri Kamlesh Singh Chouhan Joint Secretary to Government, Mining (Group-2) Department, Rajasthan, Jaipur.

2. District Collector Karauli

3. Additional Director (Mining) Mines and Geology Department, Jaipur

Divisional Commissioner
Bharatpur

True Translated Copy

Office of the District Collector Karauli

Sr. No.P-12(3)(4)(2) Minerals/2020/546 Date: 06.03.2020

Respected Divisional Commissioner
Division Bharatpur

Subject:- Original Application No.575/2019 Yaduraj Singh Jat versus State of Rajasthan before the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi

Reference:- In reference to your Letter No./ Revenue/2020/168 dated 6.3.2020.

Sir,

In sequence of the above subjected and referenced letter enclosed with the letter of the Joint Secretary to Government and in sequence of order of the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi Dated 19.02.2020 in Original Application No.575/2019 titled as Yaduraj Singh Jat versus State of Rajasthan, a point wise report is as following:-

1. Point No.1 is related with the State Pollution Control Board.

2. It is submitted in sequence of Point No.2 that out of 82 LOI approved by the Hon'ble Supreme Court vide order dated 16.11.17 for mining of minerals sand (Bajri) in the State of Rajasthan wherein only 01 LOI was approved within Karauli in favour of Shri Ramesh Chand Morani over an area of 894.5 Hec. situated near Village Hadoti Tehsil Sapotra. The mining work was shut down from dated 27.05.2016 in the said LOI in compliance of order of the Hon'ble Green Tribunal Bhopal dated 24.05.2016.

   In sequence of order dated 03.05.2018 passed in the Civil Writ Petition No.9458/2017 instituted before the Hon'ble High Court of Jaipur, this office from dated 17.07.2018 formed a joint special investigation team comprising of the

departments such as Mining, Forest, Transport and Police Department. The said joint team regularly takes action against the illegal mining/transportation/storage of mineral bajri over mining spot in District Karauli specially in Village Hadoti situated in Tehsil Sapotra and in the Banas river flowing through the nearby areas. In addition, joint chowkis of police and mining department have been setup throughout the district in Village Bukna Mod, Chaudagao (Jodli Mod), Raneta and Gulab Kothi and Narauli Dong Tehsil Sapotra and at present check post and pickets have been setup in villages such as Chamarpura, Fatehpura, bridge connecting between Hadoti and Bhuri Pahadi, Panwarpura river and Baroda Gajrajpal thereafter CCTV cameras have been installed. After setup of the said check posts the illegal mining/transportation of mineral bajri has become almost insignificant.

In addition, continuous effective actions have been taken by the Police Department, Mines Department, Revenue Department, Transport Department, Forest Department by jointly establishing co-ordination amongst them from time to time in order to prevent illegal sand mining and transportation within the area. In addition, in the weekly meeting organised at the District level also the officers of the Revenue, police, mines, forest and Transport Departments are directed for taking effective actions by establishing co-ordination amongst them. In the said relation, the actions taken this year are as following:-

Period from 01.04.2019 till 06.03.2020

S. No.	Name of Department	No. of cases in which action was taken	Amount recovered in the cases, amount in Lakhs	No. of cases in which FIR was lodged	Special Remarks

1.	Mines Department	257	141.18	8	Illegal mining-2 Illegal transportation-247 Illegal storage-6
2.	Police Department	185	-	Cases-33 207 M.V. Act 130 38 Police Act 27	
3.	Transport Department	98	9.12	-	Truck-32 Trailor-8 Tractor-58

Enclosures:- Copy of the report of Mines, Police and Transport Department.

(Sudarshan Singh Tomar)
Additional District Collector
Karauli

Sr. No./Even/2020/ Date: 06.03.2020

Photocopy to:-

1. Respected Joint Secretary Mines Department, Mines (Group-2) Rajasthan, Jaipur.

Additional District Collector
Karauli

True Translated Copy

Office of the District Transport Officer, Karauli

Sr. No.2700 Date:- 06.03.2020

To,

The Respected District Collector,

Karauli

Subject:- Original Application No.575/2019 titled as Yaduraj Singh Jat versus State of Rajasthan before the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi

Reference:- In reference to the Joint Secretary to Government, Mining (Group-2) Department, Rajasthan Jaipur Letter no.P-11(1)(82) Mining/Group-2/2020 Dated 06.03.2020.

Sir,

It is respectfully submitted in the above subjected matter that by preparing the following report in respect of the action taken by the flying squad on the overload transportation of sand within the district from the month of April 2019 till February 2020 is being sent for your kind perusal:-

S. No.	Type of vehicle	No. of Challan	Amount (in Lakhs)
1	Truck	32	2.41
2	Trailor	8	1.49
3	Tractor	58	5.22
	Total	98	9.12

Sd/- District Transport Officer
Karauli (Rajasthan)

True Translated Copy

Government of Rajasthan

Office of the Mining Engineer, Mines & Geology Department, Karauli

Office of the District Council and Khanij Bhawan near City Park

Mail Id-me.karoli@rajasthan.gov.in tele No.07464-250202

Sr.No.M.E./Kar./Bajri SIT/2020/34 **Date: 06.03.2020**

Subject:- Original Application No.575/2019 titled as Yaduraj Singh Jat versus State of Rajasthan before the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi

Reference:- In reference to your Letter No.P-12 (3)(4)(2)Mineral/2020/542 dated 06.03.2020.

Sir,

It is respectfully submitted in the above subjected matter that a point wise reply in compliance of the order dated 19.02.2020 passed in the Original

Application No.575/2019 titled as Yaduraj Singh Jat versus State of Rajasthan before the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi is as following:-

1. In the point No.1, the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi has demanded for a report in respect of the case from the Rajasthan State Pollution Control Board and Madhya Pradesh State Pollution Control Board and since the same is not related with this office therefore no remarks are expected.

2. Remarks in respect of Point No.2 are as following:-

   The petitioner Shri Naveen Sharma instituted a Special Leave to Appeal No.34811/2013 before the Hon'ble Supreme Court against the order dated 21.10.2013 passed by the Hon'ble High Court of Jaipur in DBCMA No.250/2013 and the Hon'ble Supreme Court by passing an order dated 16.11.2017 in the

said instituted S.L.P. restrained from carrying out mining of mineral bajri by the 82 LOI approved in the State of Rajasthan wherein only 01 LOI was approved within Karauli in favour of Shri Ramesh Chand Morani over an area of 894.5 Hec. situated near Village Hadoti Tehsil Sapotra. The mining work was shut down from dated 27.05.2016 in the said LOI in compliance of order of the Hon`ble Green Tribunal Bhopal dated 24.05.2016.

After the said order, consequent to stay on the mining activities over the legal sources of mineral bajri complaints regarding illegal mining/transportation of mineral bajri began to be received by the office and on which the office continued to take action holding the mineral bajri as illegal under the provisions of The Rajasthan Minor Mineral Concession Rules, 1986.

Thereafter, in compliance of the directions given in the order dated 03.05.2018 passed in the SBCWP No.9458/2017 titled as Sanjay Kumar Garg versus State of Rajasthan instituted before the Hon'ble High Court of Jaipur in order to prevent illegal mining/transportation/storage of mineral bajri vide the order of the District Collector Karauli dated 17.07.2018 a joint special investigation team was formed comprising of the mines, forest, transport, revenue and police departments.

The said joint team regularly takes action against the illegal mining/transportation/ storage of mineral bajri over mining spot in District Karauli especially in Village Hadoti situated in Tehsil Sapotra and in the Banas river flowing through the nearby areas.

In addition, joint chowkis of police and mining department have been setup

throughout the district in Village Bukna Mod, Chaudagao (Jodli Mod), Raneta and Gulab Kothi and Narauli Dong Tehsil Sapotra and joint check post of the mining department have also been setup which are regularly being inspected by the District Collector, Superintendent of Police and the Mining Engineer, Karauli.

According to the directions the District Collector and the Superintendent of Police for the purpose of ensuring complete compliance of the order of the Hon`ble Court in place of the chowkis setup in the said manner at present check post and pickets have been setup in villages such as Chamarpura, Fatehpura, bridge connecting between Hadoti and Bhuri Pahadi, Panwarpura river and Baroda Gajrajpal thereafter CCTV cameras have been installed. After setup of the said check posts the illegal mining/transportation

of mineral bajri has become almost insignificant.

The details of the action taken by the office in compliance of the order of the Hon'ble Supreme Court dated 16.11.2017 against the illegal mining/transportation of mineral bajri is as following:-

S. No.	Details	Illegal mining	Illegal transportation	Illegal storage	Total cases	Amount recovered (in lakhs)	FI lod
1	Dated 16.11.17 till 31.03.2018	0	29	0	29	13.69	1
2	Year 2018-19	2	214	7	223	70.46	24
3	Year 2019-20 (Upto 06.03.2020))	2	257	6	265	141.18	8

3. In compliance of Point No.3 no remarks of the office are expected.

4. In compliance of Point No.4 no remarks of the office are expected.

Regards

Sd/-

(DS Meena)

Mining Engineer, Karauli

True Translated Copy

Office of the Superintendent of Police,
District Karauli

Sr. No.Miscl./Karauli/2020/2073 Date: 06.03.2020

District Collector and Magistrate
Karauli

Subject:- Original Application No.575/2019 titled as Yaduraj Singh Jat versus State of Rajasthan before the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi

Reference:- In reference to your Letter No.P-12 (3)(4)(2) Mineral/2020/544-45 dated 06.03.2020.

Sir,

It is respectfully submitted in the above subjected referenced matter that the following actions were taken during the year 2019 and 05 March 2020 in relation to prevention of illegal mining/ transportation of sand being carried out over Banas river/Chambal river in District Karauli, which are being sent for your kind perusal:-

Information in respect of illegal sand during the year 2019

Cases	207 M.B. Act	38 Police Act
29	109	22

Information in respect of illegal sand during 01.01.2020 till 05.03.2020

Cases	207 M.B. Act	38 Police Act
04	21	05

In compliance of the order dated 19.02.2020 passed by the Hon'ble Supreme Court in Special Leave Petition (Civil) No. 10587/2019 titled as Mineral Bajri Lease LOI Holders versus State of Rajasthan it was decided for organizing a meeting of the S.I.T. at the District level under the Chairmanship of the District Collector on

29.02.2020 in the office of the Sub-Division Officer Sapotra time at 2:00PM.

In compliance of said decision, on 29.02.2020 time at 10:00AM I the Superintendent of Police and District Collector Karauli, Additional Superintendent of Police, Karauli, Sub-Division Officer Sapotra, Mining Engineer Karauli and all the other concerned District Level S.I.T. Members /Officers jointly for the sake of prevention of illegal mining/transportation of mineral bajri within Tehsil Sapotra conducted inspection of the permanent check post of RAC setup at Bukna Mode, Chauragaon (Jodli Mode), Raneta and Gulab Kothi.

Thereafter the joint team firstly inspected the major area of illegal mining of mineral bajri at Village Pawarpura, Tehsil Sapotra and the major road for illegal transportation of mineral bajri i.e. Village Fatehpura, Baroda Gajrajpal, Chamarpura.

After area inspection time at around 2:00PM in the office of the Sub-Division Officer Sapotra a meeting of the S.I.T. formed at the District and Police Station Level was organized under the Chairmanship of the District Collector for the sake of prevention of illegal mining/ transportation of mineral bajri. The following proposals were passed during the meeting:-

1. To establish RAC chowkis at the river area (illegal mining location of mineral bajri) Village Pawarpura and bridge situated in between Hadoti (District Karauli) to Bhuri Pahadi (District Sawai madhopur) over Banas river and the major road used for illegal transportation at Village Fatehpura, Baroda Gajrajpal and Chamarpura by removing the previously setup chowkis at Bukna Mode, Chauragaon (Jodli Mode), Raneta and Gulab Kothi so that no vehicle/machine is able to reach to the location of illegal mining of the mineral bajri and due to which there are

possibilities of decline in the illegal mining/ transportation.

2. To setup check post/barriers at at Chamarpura, Fatehpura, bridge in between Hadoti to Bhuri Pahadi, Pawarpura River and Baroda Gajrajpal for the sake of prevention of illegal mining/transportation of mineral bajri thereafter directions were issued to the Mining Engineer Karauli for the installation of CCTV cameras over those check posts so that fear is spread amongst such transporters and on which the Mining Engineer Karauli took the decision for installing CCTV cameras over the said check posts in the said manner.

3. During the meeting the S.I.T. formed at the District/Police Station Level jointly also decided to conduct atleast 4 big raids for seizure of illegal stock of mineral bajri prior

to 15 March along with taking action under section of P.D.P.P. Act against the guilty.

4. It was also decided that by identification of mining mafia involved in the illegal mining/ transportation of mineral bajri within the District thereafter to seize the vehicle/ machines used by them in the illegal mining/ transportation thereafter to lodge FIR against them in the concerned police station.

In context of the decisions taken as above for the sake of prevention of illegal bajri mining/ transportation after setup of permanent check at Hadoti Banas River Check Post, Kanwarpura Check Post, Garhi Gaon Check Post, Khushal Singh Tiraha Check Post, Baroda Gajrajpal Check Post thereafter staff from the Police Department, Mining Department and Forest Department have already been deputed over said check posts. CCTV cameras have been installed in all the

said five check posts. In addition, temporary guards have been deputed at Fatehpura, Hadoti Tiraha, Gordhanpura from P.S. Sapotra and Police Lines wherein police staff have been deputed.

Regards,

Sd/-
(Anil Kumar)
Deputy Superintendent of Police
Karauli

True Translated Copy